भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2876

18 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग की मांग में कमी

2876. श्री सतीश चंद्र दुबेः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के इस्पात उद्योग में कच्चे माल की लागत, विद्युत लागत तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण उत्पादन और मांग में कमी आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): जी नही। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस्पात के घरेलू उत्पादन एवं माँग का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

(मात्रा हजार टन में)

अवधि	उत्पादन	% बदलाव	खपत	% बदलाव
2017-18	104978	3.12%	90679	7.90%
2018-19	106560	1.51%	98708	8.85%
2018-19 (अप्रैल, 2018 - जनवरी, 2019)	91457	-	80816	-
2019-20* (अप्रैल, 2019 - जनवरी, 2020)	91480	0.03%	83896	3.81%

* अनंतिम; स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

अप्रैल, 2019 - जनवरी, 2020 (अनंतिम) के दौरान भारत में क्रूड इस्पात के उत्पादन में 0.03% की वृद्धि प्रदर्शित होती है जबकि अप्रैल, 2019 - जनवरी, 2020 (अनंतिम) के दौरान भारत में कुल फिनिश्ड इस्पात (नॉन-अलॉय+अलॉय/स्टेनलेस) की खपत में 3.8% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ख): एक नियंत्रणमुक्त और उदारीकृत इस्पात क्षेत्र में सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है जो एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए इस्पात क्षेत्र के मौजूदा परिदृश्य के अनुरूप नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करती है। सरकार ने इस्पात की माँग को बढ़ाने के लिए रेलवे, सड़कों, '2022 तक सभी के लिए आवास', हर घर के लिए नल से पानी जैसी बेहतर अवसंरचना के लिए सरकारी प्रयास के साथ-साथ स्वदेशी विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद खरीद (डीएमआई एंड एसपी) नीति, इस्पात स्क्रैप नीति, इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को लागू किया है।

****